



UNCCD का ड्राॅट एटलस

प्रलिस के ललल:

[UNCCD COP16](#), [मरुसथलीकरण से नपलने हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन \(UNCCD\)](#), शीतकालीन मानसून ।

मेन्स के ललल:

मरुसथलीकरण और भूमि क्षरण का मुद्दा और इस मुद्दे से नपलने के ललल कदम ।

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)

चर्चा में क्यों?

रललद में आयोजलत [UNCCD COP16](#) में [मरुसथलीकरण से नपलने के ललल संयुक्त राष्ट्र सममेलन \(UNCCD\)](#) और यूरोपीय आयोग के संयुक्त अनुसंधान केंद्र ने [वरल्ड ड्राॅट एटलस](#) जारी कलल, जो सूखे के जोखमल तथा समाधान पर एक व्वापक वैश्वकल प्रकाशन है ।

मरुसथलीकरण से नपलने हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCCD) क्वा है?

- इसे वर्ष 1994 में स्थापलत कलल ग्वा था, जो पर्यावरण और वकलस को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता है ।
- यह शुष्क, अर्द्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों पर केंद्रलत है, जलल्लें शुष्क भूमल के रूप में जाना जाता है, जललमें कुछ सबसे कमजोर पारस्थलतलकल तंत्र और समुदाय शामिल हैं ।
- सममेलन के 197 सदस्य देश शुष्क भूमल में जीवन कल स्थलतल सुधारने, भूमल और मृदा कल उत्पादकता बहाल करने तथा सूखे के प्रभावों को कम करने के ललल मललकर काम करते हैं ।
- UNCCD भूमल, जलवायु और जैव ववलधलता के परस्पर जुड़े मुद्दों के समाधान के ललल अन्य दो रलयो कन्वेंशनों के साथ सहयोग करता है:
 - जैव ववलधलता पर कन्वेंशन (CBD)
 - [जलवायु परवलरतन पर संयुक्त राष्ट्र फरेमवरक कन्वेंशन \(UNFCCC\)](#)

UNCCD के ड्राॅट एटलस के प्रमुख नषलकष क्वा हैं?

- **सूखे के जोखमल कल प्रणालीगत प्रकृतल:** सूखा एक प्रणालीगत जोखमल है जो वैश्वकल स्तर पर कई क्षेत्रों को प्रभावलत करता है । यह अनुमान है कल यलदवलरतमान रुझान जारी रहे तो वर्ष 2050 तक वशल्व कल 75% आबादी (लगभग 4 में से 3 लोग) सूखे कल स्थलतल से प्रभावलत होंगे ।
 - वर्ष 2022 और 2023 में 1.84 बललयलन लोग (वशल्व स्तर पर लगभग 4 में से 1) सूखे से प्रभावलत हुए, जललमें से लगभग 85% नमलन और मध्यम आय वाले देशों के थे ।
- **आर्थकल परणलम:** सूखे से कृषल, ऊर्जा उत्पादन और व्वापार पर गंभीर असर पड़ सकता है । UNCCD का दावा है कल सूखे के कारण होने वाले नुकसान कल आर्थकल लागत 2.4 गुना कम आंकी गई है, जो प्रतलवलरष 307 बललयलन अमेरकल डॉलर है ।
- **भारत में सूखे कल संवेदनशीलता:** भारत अपनी ववलधल जलवायु परस्थलतलयों और कृषल के ललल मानसून कल वर्षा पर नरलभरता के कारण सूखे के प्रतल वशलष रूप से संवेदनशील है ।
 - एटलस इस बात पर जोर देता है कल भारत कल लगभग 60% कृषल भूमल वर्षा पर नरलभर है, जललसे वर्षा के पैटर्न में उतार-चढ़ाव के प्रतल यह अतसलवेदनशील है ।
 - दकषणल भारत में वर्ष 2016 का सूखा गरीषम और शीत मानसून दोनों के दौरान असाधारण रूप से कम वर्षा के कारण था ।
 - तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण के कारण चेन्नई जैसे शहरों में जल प्रबंधन में गड़बड़ी हो गई है, जललके कारण पर्याप्त वर्षा के बावजूद गंभीर संकट उत्पन्न हो ग्वा है ।

- UNCCD की रिपोर्ट में सूखे और संसाधनों के ह्रास के लिये मानवीय गतिविधियों और कभी-कभी वर्षा की कमी को ज़िम्मेदार ठहराया गया है।

सूखा क्या है?

परिचय:

- सूखा जल की उपलब्धता में उल्लेखनीय कमी की अवधि है, जिससे जल की आपूर्ति, गुणवत्ता और मांग में असंतुलन उत्पन्न होता है। यह अवधि **संक्षिप्त या वर्षों तक चल सकती है**, जिससे पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है और भूजल स्तर कम हो जाता है।
 - वे कम वर्षा जैसे जलवायु कारकों के साथ-साथ जल निकासी, उपयोग और भूमि प्रबंधन जैसी मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं।
- मौसम के पैटर्न के कारण सूखा स्वाभाविक रूप से हो सकता है, लेकिन **जलवायु परिवर्तन के कारण इसकी आवृत्ति और गंभीरता बढ़ रही है।**

भारत में सूखे की स्थिति:

- **भारतीय सूखा एटलस (1901-2020)** के अनुसार, भारत का लगभग दो-तर्हिई हिस्सा सूखे की चपेट में है। 1.4 बिलियन लोगों वाले कृषि-आधारित राष्ट्र में सूखे से कृषि उत्पादकता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है।
 - वर्ष 1901 से 2020 के बीच भारत के लगभग 56% क्षेत्र में मध्यम से लेकर असाधारण सूखे की स्थिति रही, जिससे 300 मिलियन लोग और 150 मिलियन मवेशी प्रभावित हुए।
 - इसके अतिरिक्त फसल कृषि (1901 और 2020 के बीच) से लगभग 8.7 बिलियन अमरीकी डॉलर का अनुमानित आर्थिक नुकसान हुआ, जिससे कृषि GDP में 3.1% की कमी आई।

सूखे से निपटने के लिये उठाए गए कदम:

- एकीकृत सूखा प्रबंधन कार्यक्रम वैश्विक जल साझेदारी (Global Water Partnership- GWP) और विश्व जल संगठन के बीच एक संयुक्त पहल है।
 - यह कार्यक्रम नीतिगत, तकनीकी और प्रबंधन मार्गदर्शन प्रदान करके तथा वैज्ञानिक ज्ञान एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके सूखा प्रबंधन के कार्यान्वयन में सरकारों व हितधारकों की सहायता करता है।
- UNCCD की सूखा पहल सूखा की तैयारी प्रणालियों की स्थापना पर जोर देती है।
- प्रतिवर्ष 17 जून को **विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस (World Day to Combat Desertification and Drought- WDCDD)** के रूप में मनाया जाता है।

- UNCCD की सूखा सहनशीलता, अनुकूलन और प्रबंधन नीति (DRAMP) रूपरेखा, सूखा जोखिमों को समझने, आँकड़े एकत्र करने, समान समाधान तैयार करने हेतु सतत विज्ञान-नीति सहयोग का समर्थन करती है, ताकि अर्थव्यवस्थाओं, समाजों तथा पारिस्थितिकी प्रणालियों के लिये लचीलापन सुनिश्चित किया जा सके।

वर्ल्ड डेजर्ट एटलस की प्रमुख सफारिशें क्या हैं?

शासन:

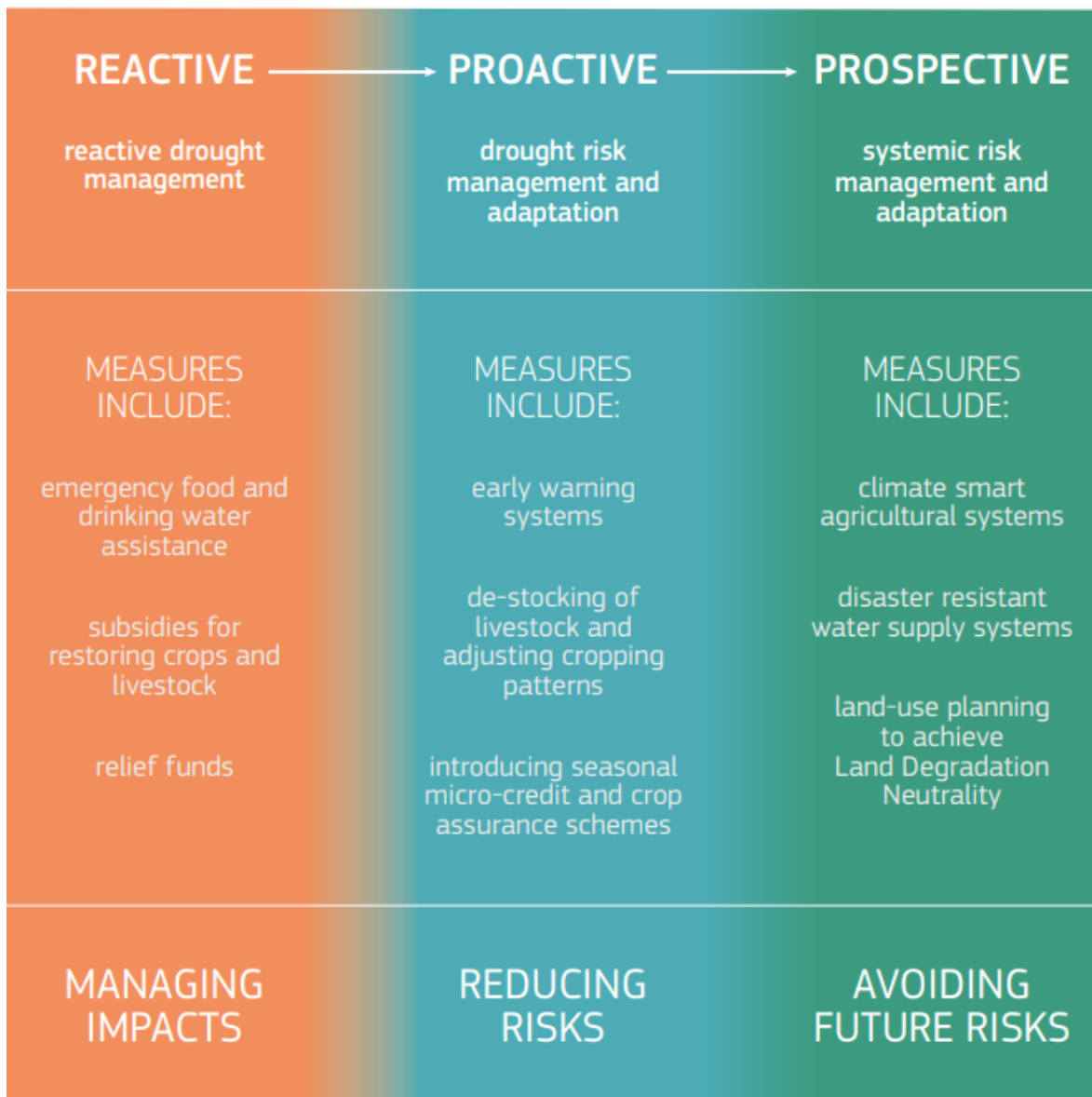
- देशों को सूखे की घटनाओं के विरुद्ध तैयारी और लचीलेपन को बढ़ाने के लिये व्यापक राष्ट्रीय सूखा योजनाएँ विकसित तथा क्रियान्वित करनी चाहिये।
- सीमाओं के पार सूखे के जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिये ज्ञान, संसाधनों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मज़बूत करना आवश्यक है।
- छोटे किसानों के लिये सूक्ष्म बीमा जैसे वित्तीय तंत्र विकसित करने से सूखे से प्रभावित कमज़ोर आबादी को सुरक्षा कवच प्रदान किया जा सकता है।

भूमि उपयोग प्रबंधन:

- सतत कृषि पद्धतियाँ, जैसे क्विनरोपण, मृदा संरक्षण, फसल विविधीकरण और कृषिवानिकी के माध्यम से भूमि पुनरुद्धार, सूखे के विरुद्ध लचीलापन बनाने के लिये आवश्यक हैं।
- ये उपाय अपवाह को कम करते हैं और तूफानी जल प्रतधारण को बढ़ाते हैं, मट्टि की गुणवत्ता में सुधार करते हैं, पशुओं के लिये छाया प्रदान करते हैं और वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं, जिससे वनस्पतियों की सूखे के प्रति लचीलापन मज़बूत होता है।

जल आपूर्ति एवं उपयोग का प्रबंधन:

- बुनियादी ढाँचे में निवेश: जल आपूर्ति और प्रबंधन हेतु बुनियादी ढाँचे में निवेश बढ़ाना, जैसे अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग तथा भूजल पुनर्भरण प्रणाली, सूखे के दौरान जल सुरक्षा बढ़ाने के लिये आवश्यक है।



दृष्टिभेन्स प्रश्न:

प्रश्न: चर्चा कीजिये कि सामाजिक-आर्थिक कारक भारत में सूखा सहनशीलता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं तथा भविष्य में सूखे के वरिद्ध तैयारी में सुधार के लिये कार्यान्वयन योग्य रणनीति सुझाइये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न (PYQ)

2014:

प्रश्न: सूखे को उसके स्थानिक वसितार, कालिक अवधि, मंथर प्रारंभ और कमजोर वर्गों पर स्थायी प्रभावों की दृष्टि से आपदा के रूप में मान्यता दी गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) के सितंबर 2010 मार्गदर्शी सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में एल नीनो और ला नीना के सम्भावित दुष्प्रभावों से निपटने के लिये तैयारी की कार्यवधियों पर चर्चा कीजिये। (2014)